tile 21st July, 1992 captioned "Once granted tail, they never come to court";

(b) if so, what is the reaction of the Government;

(c) whether it is a tact that out of five persons nabbed for heroin trafficking in 1987, four were let out on bail and all have been declared proclaimed offenders as they failed to turn up in court;

(d) whether it is also a fact that N.C.B. filed a complaint but after the arrests, High Court released two of them on bail, even before the dharge-shvet was filed;

(e) whether some more persons were also released on bail;

(f) if so, what are the reaction of Government thereto; and

(g) what steps are contemplated by Government to prevent recurrance of such incidence in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b) Yes, Sir. The attention of the Government has been drawn to the news item captioned, "Once granted bail, they never come to court" which appeared in 'Indian Express' of 21st July 1992.

(e) to (f) Reports received indicate that five persons, viz., S/Shri (1) Arjun, (2) Ali Bocus Rehmat Ali, (3) Taj Gul, (4) Khyal Asghar and (5) Abdul Bagi were arrested by the officers of Narcotics Control Bureau, Delhi, in connection with the seizure of 2 Kgs. of heroin on 6-4-1987 at the Indira Gandhi International Airport. The complaint was filed by N.C.B. before the jurisdictional court on 6-5-1987. However, before the charge sheet was filed against the accused, S/Shri Arjun and Taj Gul were released on bail by the Hon'ble High Court of Delhi on the grounds that there was no direct evidence against these two persons. The remaining three were released on bail after filing of charge-sheet. S/Shri Arjun and Taj Gul were declared as proclaimed offenders on 2-7-1988. Shri Khyal Asghar and Ali Bocus were declared as as proclaimed offenders on 4-7-1991 and 18-7-1992, respectively. Shri Abdul Bagi was acquitted by the jurisdictional court.

(g) The bail was granted by the Hon'ble Court within their competence. The law has been amended, making the bail provisions more stringent . The Government Advocates and Spl. Public Prosecutors have also been instructed to contest the bail petitions of the drug traffickers.

बैंक ऋण के लिए मार्ग निर्देश

4292. श्री अनन्त राम आमलवाल : क्या वित्त मंत्री 28 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2023 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में गठित "अध्ययन दल" की रिपोर्ट में इंगित बैंक ऋणों के लिए अनुवर्ती मार्ग निर्देश में दिए गए विभिन्न सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब से लागू किया गया है ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों ने अनुवर्ती कार्यवाही कब कब की थी ; और

(ग) क्या अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान मार्ग निर्देश पर अमल करने में कोई त्रुटियां भी पाई गई हैं, यदि हां, तो रिजर्व बैंक व वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अलग अलग की गई अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान पाई गई त्रुटियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) से (ग) टंडन समिति ने बैंक उधार संबंधी प्रणाली में परिवर्तन की सिफारिश करते हुए उद्योगों को उधार देने की भूतपूर्व प्रतिभूति उन्मुख प्रणाली के स्थान पर उनके लिए

उत्थान उन्मुख ऋण प्रणाली अपनाने के लिए कहा है । इसने उद्योग की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सुगमता के लिए कतिपय मानदण्डों की सिफारिशों के साथ ही साथ बड़े उद्योग द्वारा बैंक संसाधनों को पहल के रूप प्राप्तकर लेने पर रोक लगाने की भी सिफारिशें की । भारतीय रिजर्व बैंक ने टंडन समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिश मंजूर कर ली थीं और अगस्त एवं सितम्बर, 1975 में बैंकों को मार्ग निर्देश/अनुदेश जारी किए थे । भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गई सिफारिशों के कारगर कार्यान्वयन म और इससे उत्पन्न विषयों पर चर्चा/विचार विमर्श करने के लिए निदेशन समिति नामक एकानसमिति गठित की थी । यह समिति वर्तमान में भी कार्यरत है और इसने माल सूची और प्राप्तियों के लिए मानदण्डों का निरंतर रूप से पुनरीक्षण किया है । बैंक ऋण की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मार्गनिर्देशों के जारी करने के उपरान्त, भारतीयरिजर्व बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से विभिन्न विवेकीय अनुशासनों और मानदण्डों की अनुपालना सेसंबंधित छमाही विवरण प्राप्त हो रहे हैं । इनछमाही विवरणों में ऋणकर्ता खातोंकी समय पर पुनरीक्षा से संबंधित सूचना, उधार की पहली या दूसरी विधिको अपनाने, उधारकर्ताओं द्वारा मालसूची और प्राप्तियों से संबंधित मानदण्डों की अनुपालना और उधारकर्ताओं द्वारा तिमाही सुचनाप्रणाली की अनुपालना संबंधी विवरण शामिल हैं । इन विवरणों की भारतीय रिजर्व बक में संवीक्षा की जाती है.और बैंकों को समय समय पर सुधारात्मक औरउपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है ।

Certificate from U.S.A. on Narcotics Control

4293. SHRI PRAKASH YASH WANT AMBEDKAR: Will the Min ister of FINANCE be pleased to staet: "

(a) whether it is a fact that India gets certificate from U.S.A. on n*ar*-eoties coutrol;

(b) if so, what is the last date for, getting the certificate; and

(c) what are the consequences if India does not get the certificate from U.S.A.?

THE MINISTER OF STATE. IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Under US law, the President is required to certify annually to Congress that as illicit opium producer, India has taken steps under Indian law to prevent diversion of andillicit production of opium and is cooperating fully with the US in narcotics control. Narcotics certification is announced each March 1st. for the activities undertaken during the previous calendar year. India has been regularly receiving this certification. The denial of certification would result in the withholding of 60 per cent of US assistance to India and the US would be obliged to vote against any loan or other utilisation of funds from the IBRD, IDA and other multilateral financial institutions.

Non-payment of Gratuity to State Bank of Indore Employees

4294. SHRI RAM GOPAL YADAV: SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of retired employees who have not yet been paid their gratuity amount by the State Bank of Indore since 1987 (till date) and the Branch of their retirement;

(b) what is the total amount of inpaid gratuity involved;

(c) what are the reasons for non-settlement of their dues; and

(d). what steps have been taken by Government for expeditious set-.tlement of their dues?